

मालीवाल प्रकरण

आरोप-प्रत्यारोप

मालीवाल पर हमले के मामले में केजरीवाल के सहायक की गिरफ्तारी के बाद 'आप' और भाजपा में आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षता 'आप' की राज्यसभा सांसद स्वाती मालीवाल पर कथित हमले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार नामजद हैं। यह मामला गंभीर होता जा रहा है। यह घटनाक्रम तिहाड़ जेल से केजरीवाल की वापसी के कुछ ही दिन के भीतर हुआ जहां उनको दिल्ली एक्साइज नीति निर्धारण में भ्रष्टाचार के आरोप में बंद किया गया था। अब कथित हमले में विभव कुमार की गिरफ्तारी से विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक दांवपेंचों की शुरुआत हो गई है। इस मामले में स्वाती मालीवाल केन्द्र में हैं जिन पर दिल्ली महिला आयोग-डीसीडब्लू में नियुक्तियों में कथित अनियमिताओं के आरोप में 'एंटी-करणशन ब्यूरो' जांच कर रहा है। पहले हमले की बात स्वीकारने वाली 'आप' अब आरोप लगा रही है कि मालीवाल को इस मामले में गिरफ्तारी की धमकी पर ब्लैकमेल किया गया था। विभव की गिरफ्तारी का संबंध इस जांच से है, जिसने पहले से ही अस्थिर स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। अपने सहायक की गिरफ्तारी के विरोध में अरविंद केजरीवाल ने 'आप' विधायकों, सांसदों और समर्थकों के साथ भाजपा मुख्यालय तक एक विरोध मार्च निकाल कर विभव के साथ एकजुटता प्रदर्शित की तथा भाजपा द्वारा राजनीतिक बदला लेने का 'खुलासा' किया। प्रधानमंत्री मोदी को भेजे एक वीडियो संदेश में केजरीवाल ने कहा है कि वे एक-एक कर गिरफ्तार करने के बजाय 'आप' के सभी नेताओं को एकसाथ गिरफ्तार कर लें। केजरीवाल ने जोर दिया कि विभव और मालीवाल के खिलाफ



‘आप’ और भाजपा के बीच टकराव से दूर रहना है क्योंकि ये दोनों दिल्ली में उसके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। राजनीति में समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रकरण ऐसे समय हुआ है, जब दिल्ली में एक सप्ताह में 25 मई को मतदान है। इस बीच ‘आप’ और भाजपा के बीच टकराव विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच टकराव का अंग बन गया है। इस घटना के राजनीति पर दूरगामी परिणाम होंगे जिससे भावी चुनावों में मतदाताओं का दृष्टिकोण प्रभावित हो सकता है। फिलहाल मालीवाल पर दोषारोपण करना ठीक नहीं है क्योंकि मामला अभी अदालत के विचाराधीन है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अतीत में दिए उनके कुछ बयान अजीब लगते हैं। एक बार उन्होंने ट्वीट किया कि वे ‘सौभाग्यशाली बेटी’ हैं, लेकिन दूसरे अवसर पर उन्होंने कहा कि बचपन में उनका यौन उत्पीड़न हुआ था। दोनों पार्टियों द्वारा एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप के बाद, दिल्ली की जनता पूरे प्रकरण पर गंभीर नजर रख रही है। उसे अनुमान है कि ऐसे समाधान निकलेंगे जिनसे ‘राजनीतिक सुविधा’ के बजाय सुशासन व व्याय को वरीयता मिलेगी। भगवान बुद्ध ने एक बार कहा था, ‘तीन चीजें-सूरज, चांद और सत्य लंबे समय तक छिपाई नहीं जा सकती हैं।’ जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि मालीवाल प्रकरण एक राजनीतिक घटयंत्र है अथवा यह ‘आप’ पार्टी सदस्यों पर हमले की रणनीति है।

आज की समस्याओं
का समाधान केवल
आध्यात्मिक हो
सकता है और हमने
युवा जनसंख्या को
आध्यात्मिकता से
वंचित रखा है।
हमारी शिक्षा बहुत
खतरनाक ढंग से
जीवन विरोधी हो
गई है।



आचार्य प्रशांत
(लेखक, वेदांत
शिक्षक हैं)

भारत के महत्वपूर्ण मुद्रे स्थायी, परिवर्तनकारी परिवर्तन के लिए व्यावहारिक कारबाई और सामूहिक मानसिकता में बदलाव की मांग करते हैं। भारत को विभिन्न क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली अनेक चुनौतियों का समाना करना पड़ता है। इन समस्याओं को समाज, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि से संबंधित मानना आकर्षक लगता है, लेकिन अनिवार्य रूप से सभी समस्याओं की जड़ें मनुष्य के दिमाग में होती हैं और स्वयं की पर्याप्त समझ की कमी से उत्पन्न होती हैं। इसलिए समाधान बाहरी और आंतरिक दोनों ढोमेन में होने चाहिए। आइए भारत को परेशान करने वाले पांच प्रमुख संघर्षों और चुनौतियों पर नजर डालें। भविष्य के लिए सभी उत्पत्तियों में से यह समाजात्मकों का

ਮੁਹੱਲੀ ਕੀ ਲਵੂ

लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण का मतदान समाप्त होने के बाद अब 25 मई और 1 जून को बाकी दो चरणों के चुनाव के बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे का सबको बेसब्री से इंतजार है। वैसे चुनाव परिणाम के संकेत शेयर बाजार से मिलने लगे हैं। पूंजी बाजार अत्यंत डरपोक होता है और किसी भी अफवाह पर वह तुरंत अपनी प्रतिक्रिया बता देता है। इस चुनाव में जो लोग परास्त होने जा रहे हैं उन्हें कोई लहर नजर नहीं आ रही है, जबकि कुछ राज्यों को छोड़कर देशभर में मोटी की लहर हिलोरें मार रही है। भाजपा तथा उसके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन भी इस बार चुनाव में भरपूर मेहनत कर रहा है। भाजपा और एनडीए योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से चुनाव अभियान चला रहा है। जहां तक शेयर बाजार और अवैध रूप से चलने वाले सद्वा बाजार का सवाल है, तीसरे राउंड के बाद जो शेयर बाजार धड़ाम से गिर पड़ा था, वही अब 4 जून के परिणाम के बाद नई ऊंचाईयां छूकर बतायेगा। स्टारियो ने भाजपा को 300 से 335 सीटें तक मिलने का अनुमान लगाया है। मतदान केन्द्रों पर खासकर मध्य वर्ग व निम्न मध्य वर्ग जिस उत्साह के साथ मतदान कर रहा है, उससे भाजपा नेताओं का यह अनुमान सही सिद्ध हो सकता है कि देश में सत्ता-समर्थक लहर है।

अमेरिका-ईरान संबंध और भारत

भारत ने चाबहार बंदरगाह समझौते के माध्यम से ईरान के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है। उसे अमेरिकन सरोकारों की पृष्ठभूमि में क्षेत्रीय हितों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलन बनाना होगा।



ऐसे में ईरान के साथ इस समझौते पर हस्ताक्षर कर नई दिल्ली ने इस क्षेत्र में चीन-पाकिस्तान धुरी का मुकाबला करने की बेहतरीन संभावनायें तैयार की हैं। जहां भारत को चीनी खतरों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका से संबंध बनाए रखने और मजबूत करने की जरूरत है, वह ह उसे क्षेत्रीय सरोकारों को देखते हुए ईरान के मामले में अमेरिकी सरोकारों से स्वयं को अलग रखना होगा। यदि अमेरिका केवल अपने द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय दृष्टिकोण को महत्व दे तो भारत अमेरिका का 'अंध समर्थक' नहीं बना रह सकता है। यह भारत द्वारा निर्णय लेने में अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' बनाए रखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। भारत ने रूसी तैल खरीदने तथा मास्को के साथ नजदीकी संबंध बनाए रखने में इसी नीति का अनुसरण किया है, हालांकि इसके साथ ही उसने यूक्रेन की घटनाओं पर भी चिन्ता प्रकट की है।

वैसे अमेरिका ने भारतीय दृष्टिकोण और मजबूरियों को समझा है जो किसी प्रकार अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचाने को लक्षित नहीं थीं। वह केवल अपने हितों की ही रक्षा करना चाहती थीं। इसलिए भारत ने ऐसे मामलों में कोई बयानबाजी नहीं की। वर्तमान स्थितियों को देखते हुए खासकर ईरान के मामलों में आक्रामक बयानती से बाइडेन प्रशासन अपना ही नुकसान करेगा। इसलिए उसे चाबहार बंदरगाह के रखरखाव के दस वर्षीय समझौते के बारे में भारत और ईरान की मजबूरियों पर समग्र रूप से गौर करना चाहिए। अमेरिकी अधिकारी के बयान को इसी पृष्ठभूमि में देखा जाना चाहिए। ईरान से भारतीय समझौते के बारे में सवाल का जवाब मांगने पर उसने कहा, ‘अपने कई बार अनेक मामलों में हमारा दृष्टिकोण देखा है। इसका अर्थ है कि ईरान से बिजनेस करने वाले किसी उद्यम को यह पता होना चाहिए कि वे स्वयं को प्रतिबंधों के संभावित खतरे के सामने रख रहे हैं।’ वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका अपने दृष्टिकोण पर बना रह सकता है, पर भारत को भी अपने हितों को देखते हुए काम करना होगा। भारत और अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में इस विरोधाभास को समझते और एक सीमा तक स्वीकार करते हैं। अमेरिका अच्छी तरह जानता है कि भारत के ईरान के साथ रणनीतिक समीकरणों का उद्देश्य अमेरिकी हितों को कमज़ोर करना नहीं है।

जटिल चुनौतियों से नीति परिवर्तन

रचनात्मक रूप से जवाब देना शामिल होगा।
यह मर्त्तविद्वित है कि जलवाया परिवर्तन

यह सवालावदत ह कि जलवायु परावरतन एक मानवजनित घटना है। लद्धाख पहले से ही जलवायु परिवर्तन के कारण क्षेत्र की परिस्थितिकी में होने वाले स्पष्ट बदलावों को लेकर अंदोलनरत है। यदि भारत ने तुरंत सुधारात्मक कदम नहीं उठाए तो पांच साल बहुत लंबा समय है। इस मुदे पर जन जागरूकता की भवावह कमी है जिसके कारण राजनीतिक निष्क्रियता हो रही है। हम देश को ऐसे वाली भयानक गर्मी की लहरों से निपटने की योजना कैसे बना रहे हैं? फसल की घटती पौधावार और चरम मौसम की घटनाओं से गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हम नहीं जानते कि जिस जहरीली हवा का हम उपभोग कर रहे हैं या जिस जल संकट का हम सामना कर रहे हैं उसका स्रोत क्या है? हम वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर कार्बन-उत्सर्जक बुनियादी ढांचे के निर्माण से हिमालय को बर्बाद करना जारी रख रहे हैं, यह जानते हुए भी कि इससे अनियमित बारिश के पैटर्न, ग्लेशियरों के पिघलने और अंततः जीवन का नियम तो नहीं है ताकि जल नहीं है।

अंधी लालसा इस अंधे कि उपभोग किसी के सफलता का सूचक है। धारणा के साथ हमारी आकार आत्म-विनाश 5 वर्षों में, हमें मानव द इस सबसे बड़े खतरे -जागरूकता कार्यक्रमों और साथ ही आत्म-क्रिमों के माध्यम से पृष्ठुर्ण जीवन दर्शन को में वास्तविक प्रयासों है। वही वासना जो ग्रह मकी देती है, पृथ्वी पर के अधिकारों का भी अधिकारों के उल्लंघन, और जैव विविधता स्थाएँ - सभी एक ही गी हैं। जब हम पशु करते हैं, तो दुर्भाग्यवश के बुनियादी अधिकार छठे 50 वर्षों में ग्रह पर यों में से लगभग 50 ल

हिंसक मानवीय कार्रवाई है। प्रतिदिन 100-1000 प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। साथ ही, यह प्राकृतिक विलुप्ति दर से 100 से 1000 गुना तेज है। भारतीय और मनुष्य के रूप में, हमने पूरे ग्रह के खिलाफ जिस तरह का कालीन प्रजातिनाशक लॉन्च किया है, उसके साथ हम शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से जीवित रह सकते हैं। अपने पैमाने और करूरता में, यह पृथ्वी पर अब तक देखी गई किसी भी हिंसा की कार्रवाई से कहीं अधिक है।

यह देखना विशेष रूप से खेदजनक है कि भारत, अपनी अहिंसा के साथ, जीवन रूपों के प्रति अत्याचार के सबसे बुरे अपराधियों में से एक है। चाहे वह मांस निर्यात हो, डेयरी उद्योग का विस्तार हो, या तथाकथित विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से पशु आवासों का संगठित विनाश हो, यह सभी के लिए केवल विनाश का संकेत है। अगले 5 वर्षों में, मैं इस मार्चें पर सीधी और मजबूत कार्रवाई देखना चाहता हूँ जो केवल सार्वजनिक चेतना की उत्तेजना के परिणामस्वरूप हो सकती है। वही वासना जो एक दो तरफ से उत्तीर्णी होती है, उस-

पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणियों के अधिकारों का भी हनन करती है। . पशु अधिकारों के उल्लंघन, पारिस्थितिकी हानि और जैव विविधता विलुप्त होने की समस्याएँ - सभी एक ही स्रोत से उत्पन्न होती हैं। जब हम पशु अधिकारों की बात करते हैं, तो दुर्भाग्यवश आज यह जीवित रहने के बुनियादी अधिकार के लिए संवर्धन है। पिछले 50 वर्षों में ग्रह पर सभी जीवित प्रजातियों में से लगभग 50% विलुप्त हो गई हैं। इसका अधिकांश कारण हिंसक मानवीय कार्रवाई है। प्रतिदिन 100-1000 प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। साथ ही, यह प्राकृतिक विलुप्ति दर से 100 से 1000 गुना तेज है।

भारतीय और मनुष्य के रूप में, हमने पूरे ग्रह के खिलाफ जिस तरह का कालीन प्रजातिनाशक लॉन्च किया है, उसके साथ हम शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से जीवित रह सकते हैं। अपने पैमाने और क्षर्ता में, यह पृथ्वी पर अब तक देखी गई किसी भी हिंसा की कार्रवाई से कहीं अधिक है। यह देखना विशेष रूप से खेदजनक है कि भारत, अपनी अहिंसा के साथ, जीवन रूपों के प्रति अल्पात्मक होने वाले अधिकारों में से

एक है। चाहे वह मांस नियात हो, ड्यूरी उद्योग का विस्तार हो, या तथाकथित विकासात्मक गतिविधियों के माध्यम से पशु आवासों का संगठित विनाश हो, यह सभी के लिए केवल विनाश का संकेत है।

अगले 5 वर्षों में, मैं इस मोर्चे पर सीधी और मजबूत कार्रवाई देखना चाहता हूं, जो केवल सार्वजनिक चेतना की जागृति के परिणामस्वरूप हो सकती है। भारत की शिक्षा की स्थिति पर सार्वजनिक ऑकॅडेंट दर्शाते हैं कि देश कितने गहरे संकट में है। स्कूली छात्रों की बुनियादी मात्रामें और भाषाई क्षमताओं पर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, कॉलेज उत्तीर्ण छात्रों की बेरोजगारी का तो जिक्र ही नहीं किया गया है। विकसित दुनिया और विकासशील देशों की तुलना में, यह भारतीय समाज में शिक्षा को महत्व न देने की बात को उजागर करता है। आज की समस्याओं का समाधान केवल आध्यात्मिक हो सकता है और हमने युवा आबादी को आध्यात्मिकता से वंचित रखा है। हमारी शिक्षा बहुत खतरनाक ढंग से जीवन विरोधी हो गई है। मनुष्य तभी जीवित है जब वह अपने सभी असाधारणताओं में से

आप की बात

राम मंदिर पर राजनीति

सदियों से लंबित प्रकरण सुलझ कर अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है। अब सेकड़ों-हजारों सालों तक भगवान् श्रीराम का आशीर्वाद भक्तों पर बना रहेगा। विशुद्ध राजनीतिक इच्छाशक्ति व सनातन धर्म के प्रति आस्था व उसके आधार पर संघर्ष के चलते आज भगवान् राम टेंट से निकल कर विशाल मंदिर में विराजमान हो गए हैं। हालांकि, बहुत से राजनेताओं व राजनीतिक दलों को भव्य राम मंदिर का निर्माण पसंद नहीं आया है, लेकिन अब कोई भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल फिर रामलला को मंदिर से टेंट में लाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उनका यह दावा भी निरर्थक है कि अगर सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का निर्माण करते। जनता उनकी कथनी और करनी से अच्छी तरह परिचित है। सारी जनता का विश्वास है कि यदि केन्द्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार न होती तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद इसे लटकाने का भरपूर प्रयास किया जाता। जनता को अवसरवादी राजनेताओं से पूछना चाहिए कि देश के अन्य हजारों मंदिरों के बारे में उनका क्या विचार है जिनको तोड़ कर मस्जिदें बना ली गई थीं। भारत की अधिकांश हिंदू जनता अब जाग गई है और उसे भ्रमित करना असंभव है।

पर उसे भ्रमित करना असंभव है।

जमानत का प्राविधान

जमानत का प्रविधान लंबे समय से विवादास्पद रहा है। व्यापक भ्रष्टाचार, बेर्इमानी और अनैतिक कृत्यों के चलते अदालतें और जेलें हमेशा व्यस्त रहती हैं। अधिकांश आरोपी जनसेवकों के लिए जमानत मिलना मानो एक समान्य बात हो गई है। वे जेल की सलाखों के पीछे रहकर भी अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की योजना बनाते रहते हैं। अदालतें जमानत देकर एक तरह से उह्नें और आजादी प्रदान दे देती हैं। विडंबना है कि अदालतें जिन अपराधियों को सजा देती हैं, उनमें से अनेक जमानत पर बाहर आकर फिर से वही या उससे भी असामन्य आपात्कालीन होते हैं। यह अदालतों में तरीखें पड़ती रहती हैं और जमानत पर रिहा आरोपी अपने काम-धंधे निपटते रहते हैं। यह सब देखकर आम जनता के मन में निराशा और हताह पैदा होती है। आम आदाम सोचता है कि जो लोग बड़े पैमाण पर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जमानत पर छूट जाएंगे अपनी गतिविधियों को जारी रखेंगे। इसे देखते हुए न्यूप्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। जमानत की शर्तें सख्त होती हैं। चाहिए ताकि जो लोग समाज व नुकसान पहुंचाते हैं उह्नें आसान से छूट न मिले। न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेज़ी लाने वाला असामन्यता है।

महिला उत्पीड़न

देश की राजधानी में मुख्यमंत्री के आवास पर एक राज्यसभा सांसद के साथ बदलसलूकी का मामला सामने आने पर आम आदमी पार्टी-आप की लोपापोती अत्यधिक चिन्ता का विषय है। पुलिस विभाग को निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई कर दोषी को कठोरतम सजा दिलानी चाहिए। चिन्ता की बात है कि राजनीतिक दल महिला उत्पीड़न के मामलों में भी अपनी दलगत राजनीति अपनाने से बाज नहीं आते हैं। राजनीतिक दलों को यह प्रवृत्ति बदलना होगी ताकि महिला अस्मिता व महिला उत्पीड़न के सवाल पर सारा देश एक साथ खड़ा हो सके और महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। मालीवाल प्रकरण में यह भी चिन्ता की बात है कि केजरीवाल ने आरोपी को बचाने का न केवल भरपूर प्रयास किया, बल्कि इसके लिए एक और महिला मंत्री को आगे कर दिया है। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की महिला मुख्यमंत्री भी संदेशखाली में महिला उत्पीड़न को संकुचित राजनीतिक व चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से देख रही हैं। महिला उत्पीड़न में कुछ महिलाओं की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका चिन्ता का विषय है।

- वीरेन्द्र कुमार जाटव, दिल्ली

